



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 आषाढ़ 1947 (श0)

(सं0 पटना 1177) पटना, मंगलवार, 1 जुलाई 2025

सं०11/आ०वि०-07/2019-11935/सा.प्र.
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

1 जुलाई 2025

विषय:— राज्य के विभिन्न सेवाओं/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए वेतन स्तर के आधार पर निर्धारित न्यूनतम कालावधि में संशोधन के संबंध में।

- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7433 दिनांक-05.06.2018 द्वारा 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्याधीन सेवाओं के पद सोपान में वेतन स्तर (पे-लेवल) आधारित व्यवस्था लागू करते हुए न्यूनतम कालावधि का निर्धारण किया गया है।
- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-635 दिनांक- 10.01.2024 द्वारा संकल्प संख्या-7433 दिनांक-05.06.2018 में विभिन्न वेतन स्तरों से उच्चतर वेतन स्तर में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि में आंशिक संशोधन किया गया है।
 - राज्याधीन सेवाओं में वेतन स्तर-4 के अन्तर्गत कार्यरत कतिपय संवर्ग के कर्मी (यथा- उच्चवर्गीय लिपिक एवं आशुलिपिक संवर्ग) द्वारा वेतन स्तर-07 में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को कम करने के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदन तथा इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के CSSS का संकल्प संख्या-15/1/2014-CS-11-(C), दिनांक-16.04.2015, झारखण्ड राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या-154, दिनांक-10.03.2023, दिल्ली सरकार की अधिसूचना संख्या-275, दिनांक-10.05.2022 में निर्धारित कालावधि की समीक्षा के आधार पर पाया गया कि वेतन स्तर-4 से वेतन स्तर-7 में प्रोन्नति के लिए न्यूनतम कालावधि बिहार राज्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
 - उपर्युक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433 दिनांक-05.06.2018 यथा संशोधित संकल्प संख्या-635 दिनांक-10.01.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए वेतन स्तर-4 से 7 के बीच विभिन्न वेतन स्तरों से उच्चतर वेतन स्तर में प्रोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम कालावधि को निम्न रूप में संशोधित किया जाता है —

क्र०	प्रोन्नति के लिये निर्धारित (Pay Level)		न्यूनतम अर्हक सेवा (संशोधित कालावधि)
	से	तक	
1	4	5	3 Year
2	5	6	3 Year
3	6	7	4 Year

5. सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-7433 दिनांक-05.06.2018 यथा संशोधित संकल्प संख्या-635 दिनांक-10.01.2024 के प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे एवं इस संकल्प में किए गए अन्य प्रावधान यथावत् रहेंगे।

6. यह प्रावधान निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० बी० राजेन्दर,
अपर मुख्य सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1177-571+500-डी०टी०पी०।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>